



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]
No. 76]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

जांच शुरुआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषय:- अमरीका, ईयू, चेक गणराज्य और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइनाइड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं० 15/9/2003-डीजीएडी-1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने अमरीका, ईयू, चेक गणराज्य और कोरिया गणराज्य (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइनाइड (जिसे तत्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 15 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना सं० 8/1/99-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तु पर दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० 134/99-सीमाशुल्क द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने 7 मार्च, 2000 को अन्तिम जांच परिणाम निकाले और दिनांक 31 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 10/2001-सीमाशुल्क द्वारा यथासंशोधित दिनांक 6 जून, 2000 की अधिसूचना सं. 83/2000 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. समीक्षा के लिए अनुरोध

अतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पहले समाप्त न किया जाए तो वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा।

और अतः उपरोक्त नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त उपाय की समाप्ति की तारीख से पूर्व उचित समयावधि के भीतर समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग ने विधिवत पुष्टिकृत याचिका के जरिए प्राधिकारी से ऐसी समीक्षा के लिए अनुरोध किया, निर्दिष्ट प्राधिकारी मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा कार्रवाई की शुरुआत पाटन की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की जाँच करने के लिए उचित होगी और यदि शुल्क समाप्त अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाएं तो क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. समीक्षा के लिए आधार

यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए है। यह अनुरोध इन आधारों पर किया गया है कि कोरिया से हुए आयातों के कारण पाटन में वृद्धि हुई है और अन्य देशों के विरुद्ध उपायों की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचने की संभावना रहेगी।

आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ दावा किया है कि कोरियाई निर्यातकों ने इस उत्पाद के अपने विश्व निर्यातों में काफी वृद्धि की है और उनकी कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति मालूम हुई है जबकि प्रमुख निर्यातक देशों में बढ़ती हुई कीमत की प्रवृत्ति मालूम हो रही है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि जबकि कोरिया और ईयू में उत्पादक और निर्यातक भारत को उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर कर रहे हैं, और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को रद्द कर दिया जाता है तो अमरीका और चेक गणराज्य में उत्पादक और निर्यातक पाटन का सहारा लेंगे। आवेदक दावा करते हैं कि अमरीका और चेक गणराज्य में उत्पादक/निर्यातक कुछेक अन्य देशों को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का निर्यात कर रहे हैं।

आवेदक का यह भी दावा है कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु की मौजूदा क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से बहुत ज्यादा हैं जो यदि एक बार पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाता है।

आवेदक दावा करते हैं कि भारतीय उत्पादकों की स्थिति लक्षित न्यूनतम कीमत निर्धारण द्वारा और अधिक गम्भीर बन गई है क्योंकि जिन कीमतों पर भारत में उक्त सामग्री का आयात किया जा रहा है वे कीमतें इन निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को किए जा रहे निर्यात की कीमत की तुलना में काफी कम हैं।

4. जांच शुरूआत

समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा 7 मार्च, 2000 को अधिसूचित प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों और 31 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 10/2001-सीमाशुल्क द्वारा यथा संशोधित 6 जून, 2000 की अधिसूचना सं. 83/2000 द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक शुल्क की समीक्षा करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार समीक्षा शुरू करते हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा जांच में शामिल उत्पाद सम्बद्ध देश के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम साइनाइड है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष 283711 के अंतर्गत वर्गीकृत है और जिस पर 9.1.2004 से 20% का मूल शुल्क लागू है। यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है। सोडियम साइनाइड एक पूर्णतः मूल अकार्बनिक रसायन है। इसका विनिर्माण हाइड्रो साइनिक एसिड (एचसीएन) की कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः उद्योगों, जैसे रंजक मध्यवर्ती, इलैक्ट्रो प्लेटिंग रसायनों और ऊष्मा उपचार लवणों के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

6. प्रक्रिया

इस जांच से यह निर्धारित होगा कि क्या ये उपाय समाप्त करने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति के लिए निरंतर शुल्क लगाया जाना आवश्यक है और यदि शुल्क को हटा दिया जाए तो क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति या दोनों कार्य होने की संभावना है।

- (i) इस समीक्षा में 7 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 8/1/99-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।
- (ii) इसमें शामिल देश अमरीका, ईयू, चेक गणराज्य और कोरिया जन.गण. हैं।
- (iii) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 है।
- (iv) इस समीक्षा में उपर्युक्त नियम के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6.1 सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु पृथक रूप से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011
फैक्स: 91-11-23014418

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

6.2 समय-सीमा

मौजूदा निर्णायक समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस निर्णायक समीक्षा की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा कोई प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2004

Initiation**(Sunset Review)**

Subject: Initiation of Sunset Review of the definitive anti-dumping duty imposed on import of Sodium Cyanide originating in or exported from the US, the EU, the Czech Republic and Korea RP.

No. 15/9/2003-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after refereed to as Authority) recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of Sodium Cyanide (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the US, the EU, the Czech Republic and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings of the Authority were published vide Notification No. 8/1/99-DGAD dated 15th October 1999 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Notification No. 134/99-Customs dated 27th December 1999. The Authority came out with the final findings on 7th March 2000 and definitive antidumping duty was imposed vide Notification No. 83/2000 dated 6th June 2000, as amended by notification No. 10/2001-Customs dated 31st January 2001.

2. Request for Review

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued

1080-211/04

imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions the Domestic Industry has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were remove or varied or both.

3. Grounds for review

The request is for continuation and enhancement of the antidumping duties in force. The request is based on the grounds that dumping has increased in respect of imports from Korea and the expiry of the measure against other countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant has inter-alia claimed that the Korean exporters have significantly increased their world exports of the product and their prices have been showing declining trends while major exporting countries are showing rising price trend. The applicant further claim that while producers and exporters in Korea and EU continue to export the product to India at dumping prices, the producers and exporters in USA and Czech republic would resort to dumping should the present antidumping duty be revoked. The applicant claims that producers/exporters in USA and Czech Republic have been exporting significant volumes of the product under consideration to a number of other countries at dumped prices.

The applicant further claims that the existing capacities of the subject goods in the subject countries far exceed their domestic demands which increases the likelihood of recurrence of dumping once the antidumping duty is removed.

The applicants claim that the situation of the Indian producers have been aggravated by targeted predatory pricing, given that the prices at which the material is being imported in India are quite low as compared to the export price of these exporters to other countries.

4. Initiation

Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the final

findings of the Authority notified on 7th March 2000 and definitive duty imposed by Customs Notification No. 83/2000 dated 6th June 2000, as amended vide notification No. 10/2001-Customs dated 31st January 2001.

5. Product under Consideration

The product involved in the present investigation is Sodium Cyanide, originating in or exported from the subject countries, classified under Customs subheading 283711 of Customs Tariff Act attracting 20% basic duty with effect from 9.1.2004. This classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation. Sodium Cyanide is a pure basic inorganic chemical. It is manufactured by reacting Hydro Cyanic Acid (HCN) with Caustic Soda. It is mainly used by industries such as dye intermediates, Electro-plating chemicals and for manufacture of heat treatment salts.

6. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No8/1/99-DGAD dated 7th March 2000.
- (ii) The countries involved are the US, the EU, the Czech Republic and Korea RP.
- (iii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 2003 to 31st December 2003.
- (iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

6.1 Submission of Information:

The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011. Fax: 91-11-23014418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

6.2 Time Limit:

Any information relating to the present sunset review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Sunset Review Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

6.3 Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority